



भारत - सं.रा.अमेरिका सम्बंध

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध – एक संक्षिप्त विवरण 70वीं बीपीएससी मेन्स क्लास नोट्स

लेखन:

बिहार नमन जीएस रिसर्च टीम, पटना- 16

परिचय

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुआयामी और रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर आधारित है। दशकों से, यह संबंध शीत युद्ध के दौर के दौरान एक झिझक भरे जुड़ाव से 21वीं सदी में एक व्यापक वैश्विक साझेदारी में विकसित हुआ है। 2025 में, भारत-अमेरिका संबंधों को रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विविध क्षेत्रों में मजबूत सहयोग द्वारा चिह्नित किया जाएगा। रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने, आतंकवाद का मुकाबला करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सामान्य लक्ष्यों पर आधारित है।

दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं, जिससे वे वैश्विक नवाचार में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा खरीद और रणनीतिक संवादों के माध्यम से रक्षा संबंध और भी गहरे हुए हैं, खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में।

आर्थिक जुड़ाव द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बना हुआ है, जिसमें अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए चल रही बातचीत व्यापार और निवेश के अवसरों के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि, व्यापार असंतुलन, राजनीतिक गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन संबंधी अलग-अलग प्राथमिकताएं कूटनीतिक जुड़ाव को आकार देती रहती हैं। तेजी से बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच, भारत-अमेरिका साझेदारी स्थिरता और प्रगति के स्तंभ के रूप में खड़ी है। चूंकि दोनों देश जटिल क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका सहयोग एक सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण है।

दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

- दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित संवाद बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन यात्राओं के परिणाम बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहायक रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बिडेन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत होती है। संबंधित नेताओं ने कई द्विपक्षीय बैठकें कीं और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के दौरान मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रपति बिडेन द्वारा आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलनों में भी भाग लिया, जिसमें क्वाड, I2U2 (भारत, इज़राइल, यूएसए और यूएई), लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति बिडेन के निमंत्रण पर 21-23 जून 2023 तक अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। पूर्व राष्ट्रपति बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया और व्यापार और विचार नेताओं के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने 24 सितंबर 2021 को पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट के लिए सितंबर 2021 में अमेरिका का दौरा किया था और राष्ट्रपति बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।
- राष्ट्रपति बिडेन जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8-10 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली आए। राष्ट्रपति बिडेन और पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक संपर्क गलियारे और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश (पीजीआई) के लिए साझेदारी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक गलियारों के विकास में निवेश में तेजी लाने के लिए जी20 नेताओं के एक समूह की सह-मेजबानी की।

अमेरिका से हाल ही में भारत आए प्रतिनिधित्व

- अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए 5-6 जनवरी, 2025 को भारत का दौरा किया। बैठकों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रशासन के संक्रमण से पहले चल रही पहलों को अंतिम रूप देना था।
- अपनी यात्रा के दौरान, सुलिवन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में एक महत्वपूर्ण विदेश नीति भाषण दिया, जिसमें उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका-भारत संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- एनएसए जेक सुलिवन ने जून 2024 में दूसरे ICET शिखर सम्मेलन के लिए दौरा किया।
- जनवरी 2024 में 14वें भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन टाई।

हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधित्व:

- 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने वाशिंगटन, डी.सी. में आधिकारिक कार्य यात्रा के लिए भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। नेताओं ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाने की योजना की घोषणा की, जिसमें F-35 लड़ाकू जेट के संभावित प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से भारत के अमेरिकी तेल और गैस के आयात को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए।
- 24 से 29 दिसंबर, 2024 तक भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निवर्तमान बिडेन प्रशासन और आने वाले ट्रम्प प्रशासन दोनों के अधिकारियों से बातचीत की। चर्चा का उद्देश्य एक सहज राजनयिक संक्रमण सुनिश्चित करना और रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख मुद्दों पर निरंतर सहयोग के लिए आधार तैयार करना था।
- विदेश मंत्री और सचिव ब्लिंकन ने जुलाई 2024 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान टोक्यो में मुलाकात की। इससे पहले, विदेश मंत्री और सचिव ब्लिंकन ने फरवरी 2024 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। विदेश मंत्री ने नवंबर 2022, अगस्त 2022 में ईएस के दौरान, जुलाई 2022 में बाली में जी20 एफएमएम के दौरान और जून 2022 में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान कंबोडिया में सचिव ब्लिंकन से मुलाकात की।

- रक्षा मंत्री ने चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए अगस्त 2024 और उससे पहले अप्रैल 2022 में अमेरिका का दौरा किया।
- विदेश सचिव ने 9-12 अप्रैल 2024 तक वाशिंगटन डीसी का दौरा किया और व्हाइट हाउस, विदेश विभाग, वाणिज्य विभाग, रक्षा विभाग में बैठकें कीं। उन्होंने प्रमुख थिंक टैंक और व्यापारिक समुदाय के साथ भी बातचीत की। उन्होंने पहले रणनीतिक व्यापार वार्ता और अन्य द्विपक्षीय बातचीत के लिए जून 2023 में वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था।
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) श्री अजय सूद ने क्वांटम समन्वय तंत्र की दूसरी द्विपक्षीय बैठक और संबंधित प्रयोगशाला और उद्योग यात्राओं के लिए अगस्त 2024 में वाशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया का दौरा किया। संसदीय आदान-प्रदान भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिकी कांग्रेस में मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी कांग्रेस में भारत कॉकस जिसमें सीनेट इंडिया कॉकस और भारत और भारतीय अमेरिकियों पर हाउस कॉकस शामिल है, 100 से अधिक सदस्यों के साथ अमेरिकी कांग्रेस में सबसे बड़े एकल देश कॉकस में से एक है।

रक्षा सहयोग

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग "भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नए ढांचे" पर आधारित है, जिसे 2015 में दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया था। 2016 में, रक्षा संबंध को एक प्रमुख रक्षा भागीदारी (एमडीपी) के रूप में नामित किया गया था।

- 30 जुलाई 2018 को, भारत को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण लाइसेंस अपवाद के टियर-1 में स्थानांतरित कर दिया गया। रक्षा सहयोग बहुआयामी है और इसमें नियमित संस्थागत द्विपक्षीय वार्ता, सैन्य अभ्यास और रक्षा खरीद शामिल हैं। वार्ता तंत्र के शीर्ष पर 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव करते हैं। यह वार्ता राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- 17वीं डीपीजी मई 2023 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। अमेरिका से रक्षा खरीद बढ़ रही है और इसकी राशि 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। उपयोग में आने वाले प्रमुख अमेरिकी प्लेटफार्मों में सी-130जे, सी-17, अपाचे, चिनूक, एमएच60आर हेलीकॉप्टर और पी8आई शामिल हैं।
- अन्य द्विपक्षीय वार्ता तंत्र रक्षा उत्पादन और खरीद समूह (डीपीपीजी), संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह (जेटीजी), द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता, औद्योगिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन और रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल हैं।
- 2022 से, तीन यूएस मैरीटाइम सीलिफ्ट कमांड जहाजों ने वाणिज्यिक अनुबंधों के आधार पर मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के लिए भारतीय शिपयार्ड का दौरा किया है।
- महत्वपूर्ण रक्षा समझौते जो बातचीत और सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं, वे हैं और बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (2020) और रक्षा नवाचार सहयोग के लिए आशय ज्ञापन (2018)।
- भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप जो मई 2023 में संपन्न हुआ, आपसी हित के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग और सह-उत्पादन को तेज़ करने का प्रयास करता है। भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण

पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS X) - विश्वविद्यालयों, इनक्यूबेटर्स, कॉरपोरेट्स, थिंक टैंक और निजी निवेश हितधारकों का एक नेटवर्क जून 2023 में लॉन्च किया गया था। दूसरा INDUS X शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

- सैन्य से सैन्य आदान-प्रदान उच्च स्तरीय यात्राओं, अभ्यासों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और नियमित सेवा-विशिष्ट द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से होता है। भारत के पास अमेरिका के साथ सबसे अधिक सैन्य अभ्यास हैं, जो पैमाने और जटिलता में बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यासों में युद्ध अभ्यास (सेना), वज्र प्रहार (विशेष बल), मालाबार (नौसेना), कोप इंडिया (वायु सेना) और टाइगर ट्रायम्फ (त्रि-सेवाएँ) शामिल हैं। रेड फ्लैग, रिमपैक, कटलैस एक्सप्रेस, सी ड्रैगन, मिलान कुछ ऐसे बहुपक्षीय अभ्यास हैं जिनमें दोनों देश भाग लेते हैं। INS सतपुड़ा अमेरिका की मुख्य भूमि का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज था, जब यह अगस्त 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में सैन डिएगो आया था। भारत अप्रैल 2022 में सहयोगी भागीदार के रूप में बहरीन स्थित बहुपक्षीय संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) में शामिल हुआ।

आतंकवाद विरोधी सहयोग

- आतंकवाद विरोधी सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी के स्तंभों में से एक है, जिसमें सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, परिचालन सहयोग और आतंकवाद विरोधी भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से नियमित संवाद शामिल है। 2017 में, दोनों पक्षों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पदनाम सूची प्रस्तावों पर एक संवाद शुरू किया। सीटी और पदनाम संवाद पर अंतिम जेडब्ल्यूजी 5 मार्च 2024 को वाशिंगटन डीसी में था।
- फरवरी 2025 में, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन का दौरा किया, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें मोदी ने एक सहयोगी दृष्टिकोण पर जोर दिया: "जब अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं, जब यह MAGA प्लस MIGA होता है, तो यह मेगा बन जाता है - समृद्धि के लिए एक मेगा साझेदारी।"

मेन्स सीरीज

पेपर कटिंग

संकलन

10 चुनौतीपूर्ण प्रश्न

फरवरी 2024 से फरवरी 2025

VOL 1

समसामयिक ज्वलंत मुद्दे

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

निबंध

70वीं BPSC

सम्पादकीय

50 मॉडल अभ्यास प्रश्न

बिहार नमून

तारुण रंजन
अंचल अधिकारी

अनिशा शेखर सिंह
संपादक

Bihar Naman Publication
(Bihar Naman GS: An Institute For UPSC & BPSC)

मेन्स सीरीज

पेपर कटिंग

संकलन

10 चुनौतीपूर्ण प्रश्न

फरवरी 2024 से फरवरी 2025

VOL 2

राजनीतिक व्यवस्था

भूगोल और अर्थव्यवस्था

बिहार स्पेशल

70वीं BPSC

सम्पादकीय

50 मॉडल अभ्यास प्रश्न

बिहार नमून

तारुण रंजन
अंचल अधिकारी

अनिशा शेखर सिंह
संपादक

Bihar Naman Publication
(Bihar Naman GS: An Institute For UPSC & BPSC)

सुरक्षा सहयोग

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, अमेरिका भारत में FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसमें कुल FDI इकिटी प्रवाह का लगभग 9% हिस्सा 4.99 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रवाह था। कई भारतीय कंपनियाँ अमेरिका में निवेश कर रही हैं और मूल्य जोड़ रही हैं। अप्रैल 2023 में जारी CII के एक अध्ययन के अनुसार, 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में \$40 बिलियन से अधिक का निवेश किया और 425,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा कीं।
- हमारे वित्त मंत्रालय और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सहयोग [DFC] के बीच 2022 में इकिटी निवेश, सह-बीमा, अनुदान, व्यवहार्यता अध्ययन और तकनीकी सहायता को सक्षम करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जनवरी 2024 तक, DFC का भारत पोर्टफोलियो 100 से अधिक परियोजनाओं में 4.0 बिलियन के करीब था।

दोनों देशों के बीच के संवाद तंत्र:

- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPF): 2005 में स्थापित, TPF बाजार पहुंच और व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा करता है। 14वां TPF 12 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व CIM और USTR ने किया था।
- भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद: मानकों, व्यापार करने में आसानी, यात्रा और पर्यटन, और वाणिज्यिक महत्व के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी सह-अध्यक्षता CIM और अमेरिकी वाणिज्य सचिव द्वारा की जाती है। पांचवीं वाणिज्यिक वार्ता 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- भारत-अमेरिका सीईओ फोरम: 2005 में स्थापित, फोरम वाणिज्यिक वार्ता के दौरान अलग से मिलता है और वाणिज्यिक वार्ता के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है। सीईओ फोरम की बैठक 10 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में हुई। 30 नवंबर, 2023 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव सुश्री जीना रायमोंडो ने मार्च 2023 की बैठक के अनुवर्ती के रूप में भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की एक आभासी समीक्षा आयोजित की।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों की सरकार और उद्योग को एक साथ लाने के लिए 2005 में आईसीटी पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। पिछली बैठक मई 2023 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी।
- भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी वार्ता (ईएफपी): हमारे वित्त मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के नेतृत्व में, 9वीं मंत्रिस्तरीय ईएफपी वार्ता नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 11वीं वित्तीय और विनियामक वार्ता मार्च 2023 में गांधीनगर में आयोजित की गई थी।

भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030

ऊर्जा साझेदारी (एससीईपी); और जलवायु कार्रवाई और वित्त जुटाव वार्ता (सीएफएमडी) SCEP के पाँच स्तंभ हैं:

- 1) बिजली और ऊर्जा दक्षता,
- 2) नवीकरणीय ऊर्जा,
- 3) जिम्मेदार तेल और गैस,
- 4) सतत विकास, और
- 5) उभरती हुई ऊर्जा

• एक ऊर्जा भंडारण कार्य बल स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण का समर्थन करता है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के नेतृत्व में पिछली SCEP मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई 2023 में दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी।

• वित्त वर्ष 2023-24 में हाइड्रोकार्बन व्यापार 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

• अमेरिका 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ और 2022 में ISA समझौते की पुष्टि की। अमेरिका आपदा राहत अवसंरचना गठबंधन (CDRI) का भी सदस्य है। भारत जलवायु क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच में भाग लेता है। अगस्त 2023 में भारत और अमेरिका ने लैब-टू-लैब सहयोग, पायलट प्रोजेक्ट और नवीन तकनीकों और कैपेसिटिव विकास के परीक्षण को सक्षम करने के लिए यूएस-इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म (RETAP) लॉन्च किया।

दोनों देश भारत में ई-बस निर्माताओं/ऑपरेटरों को वित्तीय गारंटी प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों फंडों के माध्यम से वित्तपोषित भुगतान सुरक्षा तंत्र पर सहमत हुए।

सितंबर 2023 में भारत में ग्रीनफील्ड अक्षय ऊर्जा, बैटरी भंडारण और उभरती हुई हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की तैनाती में तेजी लाने और पूंजी की लागत को कम करने के लिए। इस दिशा में, भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और अमेरिकी विकास वित्त निगम ने एक अक्षय अवसंरचना निवेश कोष को स्थापित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रदान करने के लिए रुचि पत्रों का आदान-प्रदान किया। निधि की शर्तों पर चर्चा चल रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष सहयोग

• अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को सितंबर 2019 में 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है। यू.एस. नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) तथा भारत के DST, MeitY तथा DBT ने AI, उन्नत संचार नेटवर्क, क्वांटम विज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण, जैव सुरक्षा तथा जैव सुरक्षा आदि में अनुसंधान सहयोग का समर्थन करने के लिए तीन अलग-अलग कार्यान्वयन व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए।

• भारत तथा अमेरिका का पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अन्वेषण में नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA), राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA), अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ मजबूत नागरिक अंतरिक्ष सहयोग है। भारत-अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग के निरंतर मूल्यांकन और बढ़ावा देने के लिए एक संवाद तंत्र "सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (सीएसजेडब्ल्यूजी)" स्थापित किया है। सीएसजेडब्ल्यूजी की पिछली बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जिसकी सह-अध्यक्षता वैज्ञानिक सचिव, इसरो नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर और विदेश विभाग के प्रधान उप सहायक सचिव ने की थी।

• इसरो और नासा पृथ्वी अवलोकन के लिए एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह, नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) विकसित कर रहे हैं। नासा/जेपीएल एलबैंड रडार का योगदान देगा, जबकि इसरो एस-बैंड रडार का योगदान देगा। एसएसी/इसरो अहमदाबाद से एस-बैंड एसएआर मई 2021 में नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) को दिया गया था। वर्तमान में, उपग्रह एकीकरण और परीक्षण के अंतिम चरण में है और 2024 के अंत में भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अमेरिकी प्रक्षेपण यान फाल्कन-9 के जरिए भारतीय उपग्रह जीसैट-20 का प्रक्षेपण सितंबर 2024 में फ्लोरिडा, अमेरिका से होने वाला है।

• इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन और चंद्रयान-3 उपग्रह मिशनों के लिए नासा/जेपीएल के डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना का लाभ उठाया। इसरो और नासा ने अप्रैल 2017 में हस्ताक्षरित ढांचे के तहत पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों में व्यावसायिक वैज्ञानिक कार्मिक विनिमय कार्यक्रम (PESEP) को सफलतापूर्वक लागू किया। जनवरी 2023 में अंतिम CSJWG चर्चा के दौरान, इसरो और नासा ने PESEP के तहत अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान को शामिल करने के दायरे का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

• जनवरी 2024 में, इसरो और नासा ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी साझेदारी को गहरा करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू करने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसरो

और नासा ने मार्च 2024 में मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग के लिए रणनीतिक ढांचे के लिए एक IA पर हस्ताक्षर किए।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) श्री अजय सूद ने क्वांटम समन्वय तंत्र की दूसरी द्विपक्षीय बैठक और संबंधित प्रयोगशाला और उद्योग यात्राओं के लिए अगस्त 2024 में वाशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया का दौरा किया।

- नासा के प्रशासक सीनेटर बिल नेल्सन ने नवंबर-दिसंबर 2023 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने नई दिल्ली में पीएमओ राज्य मंत्री और उप एनएसए के साथ बैठकें कीं। उन्होंने इसरो मुख्यालय का दौरा किया और इसरो के अध्यक्ष/अंतरिक्ष विभाग के सचिव के साथ बैठक की।

- महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, सह-विकास और सह-उत्पादन में रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को सुविधाजनक बनाने, विशेष रूप से एआई, क्वांटम, दूरसंचार, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, अर्धचालक, उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों और जैव प्रौद्योगिकी में संबंधित नवाचार पारिस्थितिकी प्रणालियों को जोड़ने के लिए 31 जनवरी 2023 को वाशिंगटन, डीसी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल [आईसीईटी] शुरू की गई थी। दूसरी आईसीईटी बैठक 13-14 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 17 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में दो एनएसए की अध्यक्षता में दूसरा आईसीईटी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वास्थ्य सहयोग

- स्वास्थ्य क्षेत्र में नए उपचार और निदान विकसित करने के लिए लंबे समय से अनुसंधान सहयोग चल रहा है। द्विपक्षीय वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (VAP) के तहत, बच्चों में दस्त का मुकाबला करने के लिए एक ROTAVAC® वैक्सीन एक भारतीय कंपनी द्वारा सस्ती कीमत पर विकसित की गई थी। VAP का 34वाँ JWG 2022 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था।

- किफायती स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करने के लिए, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नेटवर्क ऑफ लैब्स और प्रमुख अनुसंधान एजेंसियों के बीच 200 से अधिक सक्रिय सहयोग हैं। भारत अमेरिका में विपणन किए जाने वाले लगभग 40% जेनेरिक फॉर्मूलेशन की आपूर्ति करता है। भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिका में लगभग 14 स्थानों पर विनिर्माण इकाइयाँ हैं। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जानी जाने वाली भारतीय कंपनियों के पास सबसे बड़े यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुपालक दवा संयंत्र हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थान सहयोग कर रहे हैं।

• भारत-अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता का नेतृत्व भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। 2021 में, चौथी वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पांचवीं वार्ता 9-12 अक्टूबर 2023 के दौरान वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी, जिसमें महामारी की तैयारी, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, वैक्सीन विकास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधियाँ, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आदि सहित सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

- भारत ने नीतिगत अंतराल को पाटने और कोविड को समाप्त करने के लिए फरवरी 2022 में शुरू की गई अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक कार्य योजना (जीएपी) में भाग लिया।
- जून 2023 में शुरू की गई अमेरिकी पहल, कैसर मूनशॉट के तहत, भारत का डीबीटी और यूएस नेशनल कैसर इंस्टीट्यूट

EDITORIAL MAINS SERIES
February 2024 to January 2025
70th BPSC UPPSC
GS Paper & Interview
UPSC
CONGRESS TO RAISE CONSTITUTION ISSUE IN BIHAR POLLS TOO
Japan attempts a bold balancing act between guns and butter
HARVARD TO INTRODUCE BHAGARAT GITA IN CURRIC
THE NEW WATER BOMB
VIJAY SINGH
IAS Interview Faced
Sr. Manager (Projects) BHEL
Bihar Naman Publication
(Bihar Naman GS: An Institute For UPSC & BPSC)

भारत में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं को सुगम बनाता है। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के तहत भारत-अमेरिका कैंसर वार्ता की पहली बैठक 5-6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग

- शिक्षा साझेदारी भारत-अमेरिका संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसमें उच्च शिक्षा सहयोग का इतिहास और मजबूत संबंध हैं। फुलब्राइट-नेहरू द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत, दोनों देश अमेरिकी और भारतीय विद्वानों, पेशेवरों और छात्रों को फुलब्राइट-नेहरू छात्रवृत्ति और अनुदान का समर्थन करते हैं। भारत द्वारा 2015 में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (GIAN) की शुरुआत की गई थी, ताकि सालाना 1000 अमेरिकी शिक्षकों को भारत में पढ़ाने के लिए आने में सुविधा हो। GIAN को अन्य देशों में भी विस्तारित किया गया है।

- कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, प्रमाणन और मान्यता, उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मेल-मिलाप और निजी क्षेत्र के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मई 2023 में शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्य समूह (WGESD) की शुरुआत की गई थी। उच्च शिक्षा में संबंध, निजी क्षेत्र का लाभ उठाना, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, और प्रमाणन और मान्यता पर उपसमितियाँ फरवरी 2024 में शुरू की गईं।

- उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। मई 2024 तक, लगभग 3,51,000 भारतीय छात्र हैं, जिनमें से ज्यादातर STEM क्षेत्रों में स्नातक (मास्टर्स) कार्यक्रमों में हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट के अनुसार, अमेरिका में भारतीय छात्र सालाना अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 8 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं।

- सितंबर 2023 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद (IIT परिषद) और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के संघ (AAU) ने भारत-अमेरिका वैश्विक चुनौतियां संस्थान की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो सतत ऊर्जा और कृषि, स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी, अर्धचालक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण, उन्नत सामग्री, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए अग्रणी अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साथ लाएगा।

- शैक्षणिक सहयोग बहुआयामी रहा है, जिसमें संयुक्त अनुसंधान, संकाय और छात्र विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में बहु-संस्थागत सहयोगी शिक्षा भागीदारी बढ़ रही है। आईआईटी बॉम्बे शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शामिल हुआ। कई आईआईटी की अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत अकादमिक अनुसंधान साझेदारी है।

- सांस्कृतिक सहयोग समृद्ध है और विविध तरीकों से प्रकट होता है। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भारत-केंद्रित शैक्षिक कार्यक्रम हैं। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। दोनों देशों के कलाकार और तकनीकी विशेषज्ञ एक-दूसरे के संस्थानों में प्रशिक्षण लेते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, भारतीय त्योहारों और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व हिंदी दिवस, गांधी जयंती, आयुर्वेद दिवस जैसी पहलों को उजागर करने वाले कार्यक्रम समय-समय पर भारतीय प्रवासियों और भारत के मित्रों की भागीदारी के साथ आयोजित किए जाते हैं। भारतीय प्रवासी सांस्कृतिक संगठन विशेष रूप से युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में लगे हुए हैं।

- भारत और अमेरिका ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में नई दिल्ली में पहली बार 'सांस्कृतिक संपत्ति समझौते' पर हस्ताक्षर किए।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

आर्थिक साझेदारी में उल्लेखनीय विकास हुआ है। अमेरिकी दवा कंपनी एमजेन ने भारत के हैदराबाद में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र में 200 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की, जो दवा विकास के लिए एआई और डेटा विज्ञान का लाभ उठाने पर केंद्रित है। इस पहल का लक्ष्य वर्ष के अंत तक लगभग 2,000 लोगों को रोजगार देना है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तकनीकी सहयोग का उदाहरण है।

भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियाँ और विवाद (2025)

सकारात्मक प्रक्षेपवक्र के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हाल ही में एक राजनीतिक विवाद तब पैदा हुआ जब एलोन मस्क ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत में मतदाता मतदान का समर्थन करने के लिए 21 मिलियन डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया है। हालाँकि, रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत को ऐसा कोई फंड आवंटित नहीं किया गया था; इसके बजाय, यह पैसा बांग्लादेश में राजनीतिक जुड़ाव के लिए निर्देशित किया गया था। इस गलत सूचना ने दोनों देशों में संदेह और राजनीतिक बहस को हवा दी है।

1. राजनीतिक चुनौतियाँ और गलत सूचना

• एलोन मस्क से जुड़ी गलत सूचना घटना: 2025 की शुरुआत में, एक राजनीतिक विवाद तब पैदा हुआ जब एलोन मस्क ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने भारत में मतदाता मतदान का समर्थन करने के लिए 21 मिलियन डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया। हालाँकि, आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चला है कि यह धनराशि वास्तव में बांग्लादेश में राजनीतिक भागीदारी के लिए आवंटित की गई थी, न कि भारत में।

- प्रभाव: इस गलत सूचना ने राजनीतिक बहस और संदेह को हवा दी, कूटनीतिक विश्वास को प्रभावित किया और राजनीतिक आख्यान तैयार किए जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
- निहितार्थ: यह घटना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गलत सूचना की बढ़ती चुनौती को रेखांकित करती है, जिसके लिए पारदर्शी संचार और सक्रिय कूटनीति की आवश्यकता है।
- घरेलू राजनीतिक गतिशीलता: दोनों राष्ट्र जटिल घरेलू राजनीतिक परिदृश्यों का सामना कर रहे हैं जो विदेश नीति निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अमेरिका में, पक्षपातपूर्ण राजनीति व्यापार और रक्षा समझौतों को प्रभावित कर सकती है, जबकि भारत में, घरेलू चुनावी विचार विदेश नीति के रुख को प्रभावित कर सकते हैं।
- उदाहरण: घरेलू राजनीति में किसी भी कथित विदेशी हस्तक्षेप या प्रभाव से राष्ट्रवादी भावनाएँ भड़क सकती हैं, जिससे कूटनीतिक वार्ताएँ जटिल हो सकती हैं।

2. आर्थिक और व्यापार विवाद

- व्यापार असंतुलन और संरक्षणवाद: द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए चल रही बातचीत के बावजूद, व्यापार असंतुलन और संरक्षणवादी नीतियाँ विवाद के बिंदु बने हुए हैं।
- मुद्रा: अमेरिका ने अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के उच्च टैरिफ पर चिंता व्यक्त की है, जबकि भारत अपनी प्रौद्योगिकी और दवा उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच चाहता है।
- बातचीत की बाधाएं: बौद्धिक संपदा अधिकारों, डेटा स्थानीयकरण कानूनों और डिजिटल व्यापार विनियमों पर असहमति चुनौतियाँ पेश करती रहती हैं।
- वैश्विक आर्थिक रुझानों का प्रभाव: आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव सहित वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ द्विपक्षीय व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, यू.एस.-चीन व्यापार तनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत के यू.एस. के साथ व्यापार संबंधों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दोनों देश बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य को नेविगेट करते हैं।

3. रक्षा और रणनीतिक चिंताएँ

- इंडो-पैसिफिक में भू-राजनीतिक तनाव: भारत और यू.एस. के बीच रणनीतिक सहयोग इंडो-पैसिफिक सुरक्षा गतिशीलता से काफी प्रभावित है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर कार्रवाइयों के संबंध में।
- चुनौती: चीन के साथ सीधे टकराव से बचते हुए रणनीतिक हितों को संतुलित करना दोनों देशों के लिए एक नाजुक कूटनीतिक पैतरेबाज़ी है।
- निहितार्थ: यू.एस., जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ काड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) में भारत की भागीदारी को चीन के प्रभाव के लिए एक रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जाता है, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का भी खतरा है।

**Bihar Naman GS**
An Institute for UPSC and BPSC

“बिहार नमान जीएस ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक 70वीं BPSC फाउंडेशन बैच को समय से समाप्त किया है”

71st BPSC

FOUNDATION COURSE

PRELIMS | MAINS | ESSAY | INTERVIEW

Start from **11 FEBRUARY 2025** **HURRY UP!** **ADMISSION OPEN**

TIME: 8 AM - 12 PM*
Duration: 11 Month

Includes:

- MAINS ANSWER WRITING PROGRAM
- 71st PRELIMS TEST SERIES
- BOOKS / NOTES / STUDY MATERIAL
- MENTORSHIP

छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग आधुनिक सुविधाओं से युक्त होस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है।

Installment Facility	द्विमासिक के 30 दिन	20,000/-	10,000/-
	द्विमासिक के 30 से 60 दिन	15,000/-	10,000/-
	द्विमासिक के 45 से 60 दिन	15,000/-	10,000/-

8368040065
Bihar Naman GS
3rd Floor, A. K. Pandey Building,
Road No. 2, Near Dinkar Golambar, Patn- 16

Follow Us:    
www.biharnaman.in

FREE

OFFLINE
45,000/-

ONLINE
25,000/-

• रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों और रक्षा खरीद नीतियों पर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका बौद्धिक संपदा की अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा चाहता है, जबकि भारत अधिक स्थानीयकरण और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखता है।

4. मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे

• मानवाधिकार चिंताएँ और राजनीतिक आलोचना: अमेरिका ने समय-समय पर भारत में मानवाधिकार मुद्दों पर चिंता जताई है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकार शामिल हैं।

○ राजनीतिक संवेदनशीलता: भारत अक्सर ऐसी आलोचना को अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखता है, जिससे कूटनीतिक घर्षण होता है।

○ उदाहरण: भारत की आंतरिक नीतियों पर अमेरिकी सांसदों की टिप्पणियों ने कभी-कभी भारत में विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।

• वीज़ा और आव्रजन नीतियाँ: वीज़ा और आव्रजन नीतियाँ, विशेष रूप से H-1B वीज़ा कार्यक्रम के संबंध में, विवाद का विषय बनी हुई हैं। अमेरिकी आव्रजन कानूनों में परिवर्तन तकनीकी क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं।

5. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर असहमति

• जलवायु परिवर्तन संबंधी अलग-अलग प्राथमिकताएँ: नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु प्रौद्योगिकी पर सहयोग के बावजूद, भारत और अमेरिका के जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

○ मुद्दा: अमेरिका सख्त कार्बन कटौती लक्ष्यों पर जोर देता है, जबकि भारत जलवायु न्याय की वकालत करता है, जिसमें विकसित देशों से वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जाता है।

○ कूटनीतिक चुनौती: वैश्विक जलवायु मंचों में प्रभावी सहयोग के लिए इन मतभेदों को सुलझाना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

2025 में भारत-अमेरिका संबंधों की विशेषता मजबूत रणनीतिक और आर्थिक भागीदारी है, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता, व्यापार विवाद, रक्षा चिंताओं और सामाजिक मुद्दों से भी चुनौती मिलती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक कूटनीति, पारदर्शी संचार और प्रत्येक देश की घरेलू नीतियों के लिए आपसी सम्मान की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध को बनाए रखने के लिए संतुलित और रचनात्मक संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा।

न्यू पारदर्शक पर आधारित

बिहार

BPSC

नमन चतुर्थ संस्करण

(बिहार लोक सेवा आयोग)

सामान्य अध्ययन

प्रश्न पत्र-II

BEST SELLER

- बिहार विशेष
- भारत का भूगोल
- भारत की अर्थव्यवस्था
- मुख्य परीक्षा प्रश्न संग्रह (1992-2024)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- भारत की राज्य व्यवस्था
- परीक्षोपयोगी अभ्यास प्रश्न

संतोष कश्यप

Bihar Naman Publication

71st BPSC Mains Answer Writing Practice PROGRAM

MAWP

40 MAWP / TEST

20 Sectional
9 Essay
7 DI
3 Full Length
1 Optional
 English | Hindi
 Offline | Online

Start ON 16 Feb' 2025
4 pm - 6 pm

ADMISSION OPEN

FEE STRUCTURE

Hindi & English Med.-

OFFLINE 6000/- **ONLINE 4500/-**

Bihar Naman GS
 Add.: 3rd Floor, A, K. Pandey Building, Road No. 2, Near Dinkar Golambar, Rajendra Nagar, Patna, Bihar 800016

8368040065

Follow Us: www.biharnaman.in

यदि ऑनलाइन विद्यार्थी इन सभी टेस्ट की प्रिंटआउट या हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो उन्हें सभी 40 टेस्ट के लिए ₹ 1200 अतिरिक्त भुगतान करना होगा। टेस्ट उन्हें 10-10 के सेट में कुल चार बार उनके दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने 13 फरवरी, 2025 को वाशिंगटन, डीसी में आधिकारिक कार्य यात्रा के लिए भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। इस बीच दोनों देशों के बीच जो भी बातें हुई हैं या जो भी भविष्य की योजनाएं हैं, उन सभी का विस्तृत ब्यौरा दिया जा रहा है जो आपके आगामी 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।

भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य (13 फरवरी, 2025)

1. दोनों देशों के नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विशेष रूप से, डोनाल्ड जे. ट्रम्प भारत को अमेरिकी तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात बढ़ाने पर सहमत हुए, जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधों को संतुलित करना और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का समर्थन करना है।
2. स्वतंत्रता, कानून के शासन, मानवाधिकारों और बहुलवाद को महत्व देने वाले संप्रभु और जीवंत लोकतंत्रों के नेताओं के रूप में, राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधान मंत्री मोदी ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की ताकत की पुष्टि की, जो आपसी विश्वास, साझा हितों, सद्भावना और अपने नागरिकों की मजबूत भागीदारी पर आधारित है।
3. आज, राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई पहल शुरू की - "21वीं सदी के लिए यू.एस.-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना)" - सहयोग के प्रमुख स्तंभों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए। इस पहल के तहत, उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के लिए विश्वास के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए इस वर्ष प्रारंभिक परिणामों के साथ परिणाम-संचालित एजेंडे के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

रक्षा

4. यू.एस.-भारत रणनीतिक हितों के गहन अभिसरण पर प्रकाश डालते हुए, नेताओं ने कई डोमेन में फैली एक गतिशील रक्षा साझेदारी के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए, नेताओं ने इस वर्ष 21वीं सदी में यू.एस.-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए दस-वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की।
5. नेताओं ने आज तक भारत की सूची में यू.एस.-मूल रक्षा वस्तुओं के महत्वपूर्ण एकीकरण का स्वागत किया, जिसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर III, P-8I शामिल हैं। पोसिडॉन विमान; सीएच-47एफ चिनूक, एमएच-60आर सीहॉक्स और एएच-64ई अपाचे; हार्पून एंटी-शिप मिसाइल; एम777 हॉवित्जर; और एमक्यू-9बी। नेताओं ने निर्धारित किया कि अमेरिका अंतर-संचालन और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार करेगा। उन्होंने भारत की रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए भारत में "जेवलिन" एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों और "स्ट्राइकर" इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहनों के लिए इस वर्ष नई खरीद और सह-उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की। वे बिक्री शर्तों पर समझौते के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री निगरानी पहुंच को बढ़ाने के लिए छह अतिरिक्त पी-8आई समुद्री गश्ती विमानों की खरीद पूरी होने की भी उम्मीद करते हैं।
6. यह स्वीकार करते हुए कि भारत सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1) प्राधिकरण वाला एक प्रमुख रक्षा साझेदार है और एक प्रमुख क्वाड साझेदार है, अमेरिका और भारत रक्षा व्यापार, प्रौद्योगिकी विनिमय और रखरखाव, अतिरिक्त आपूर्ति और अमेरिका द्वारा प्रदान की जाने वाली रक्षा प्रणालियों की देश में मरम्मत और

ओवरहाल को सुव्यवस्थित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र विनियम (आईटीएआर) सहित अपने संबंधित हथियार हस्तांतरण नियमों की समीक्षा करेंगे। नेताओं ने अपनी खरीद प्रणालियों को बेहतर ढंग से संरेखित करने और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं की पारस्परिक आपूर्ति को सक्षम करने के लिए इस वर्ष पारस्परिक रक्षा खरीद (आरडीपी) समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का भी आह्वान किया। नेताओं ने अंतरिक्ष, वायु रक्षा, मिसाइल, समुद्री और पानी के नीचे की प्रौद्योगिकियों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी लाने का संकल्प लिया, साथ ही अमेरिका ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और पानी के नीचे की प्रणालियाँ जारी करने की अपनी नीति की समीक्षा की घोषणा की।

7. रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका-भारत रोडमैप पर निर्माण करते हुए और स्वायत्त प्रणालियों के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, नेताओं ने इंडो-पैसिफिक में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई पहल - स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन (ASIA) की घोषणा की। नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियाँ और उन्नत AI-सक्षम काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली (UAS) के सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए उन्नत स्वायत्त प्रौद्योगिकियों पर एंडुरिल इंडस्ट्रीज और महिंद्रा समूह के बीच एक नई साझेदारी का स्वागत किया, और सक्रिय टोड ऐरे सिस्टम के सह-विकास के लिए L3 हैरिस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच साझेदारी की।

8. नेताओं ने नवीनतम तकनीकों को शामिल करते हुए उन्नत प्रशिक्षण, अभ्यास और संचालन के माध्यम से सभी क्षेत्रों - वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस - में सैन्य सहयोग को बढ़ाने का भी संकल्प लिया। नेताओं ने आगामी "टाइगर ट्रायम्फ" त्रि-सेवा अभ्यास (जिसका उद्घाटन पहली बार 2019 में हुआ था) का स्वागत किया, जिसका आयोजन भारत में बड़े पैमाने और जटिलता के साथ किया जाएगा।

9. अंत में, नेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी और भारतीय सेनाओं की विदेशी तैनाती का समर्थन करने और उसे बनाए रखने के लिए नई जमीन तोड़ने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें बढ़ी हुई रसद और खुफिया जानकारी साझा करना, साथ ही संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभियानों के लिए बल की गतिशीलता में सुधार करने की व्यवस्था और अन्य आदान-प्रदान और सुरक्षा सहयोग शामिल हैं।

व्यापार और निवेश

10. नेताओं ने अपने नागरिकों को अधिक समृद्ध, राष्ट्रों को अधिक मजबूत, अर्थव्यवस्थाओं को अधिक नवीन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने के लिए व्यापार और निवेश का विस्तार करने का संकल्प लिया। उन्होंने निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को गहरा करने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य से, नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक साहसिक नया लक्ष्य निर्धारित किया - "मिशन 500" - जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक करके \$500 बिलियन करना है।

11. यह स्वीकार करते हुए कि महत्वाकांक्षा के इस स्तर के लिए नए, निष्पक्ष-व्यापार शर्तों की आवश्यकता होगी, नेताओं ने 2025 के पतन तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की पहली किश्त पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की। नेताओं ने इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने की प्रतिबद्धता जताई कि व्यापार संबंध पूरी तरह से कॉम्पैक्ट की आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस अभिनव, व्यापक बीटीए को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका और भारत माल और सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहरा करने के लिए एक एकीकृत

दृष्टिकोण अपनाएंगे, और बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने की दिशा में काम करेंगे।

12. नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए शुरुआती कदमों का स्वागत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के हाल के उपायों का स्वागत किया, जिसमें अमेरिका के हित के उत्पादों पर टैरिफ कम करना शामिल है। बोरबॉन, मोटरसाइकिल, आईसीटी उत्पाद और धातु के क्षेत्रों के साथ-साथ अल्फाल्फा घास और बत्तख के मांस जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उपाय। भारत ने अमेरिका को भारतीय आमों और अनार के निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की। दोनों पक्षों ने भारत को औद्योगिक वस्तुओं के अमेरिकी निर्यात और संयुक्त राज्य अमेरिका को श्रम-गहन निर्मित उत्पादों के भारतीय निर्यात को बढ़ाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग करने का भी वचन दिया। दोनों पक्ष कृषि वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।

13. अंत में, नेताओं ने अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के लिए एक-दूसरे के देशों में उच्च मूल्य वाले उद्योगों में ग्रीनफील्ड निवेश करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस संबंध में, नेताओं ने लगभग 7.35 बिलियन डॉलर के भारतीय कंपनियों द्वारा चल रहे निवेश का स्वागत किया उत्तरी कैरोलिना में महत्वपूर्ण बैटरी सामग्री के निर्माण में एप्सिलॉन एडवांस्ड मैटीरियल्स; तथा वाशिंगटन में इंजेक्टेबल्स के निर्माण में जुबिलेंट फार्मा। ये निवेश स्थानीय परिवारों के लिए 3,000 से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियों का समर्थन करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा

14. नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा सुरक्षा दोनों देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी नवाचार के लिए मौलिक है। उन्होंने ऊर्जा की सामर्थ्य, विश्वसनीयता और उपलब्धता तथा स्थिर ऊर्जा बाजार सुनिश्चित करने के लिए यू.एस.-भारत सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को आगे बढ़ाने में अग्रणी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में यू.एस. और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, नेताओं ने तेल, गैस और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित यू.एस.-भारत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताई।

15. नेताओं ने बेहतर वैश्विक ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। नेताओं ने संकट के दौरान आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के महत्व को भी रेखांकित किया और रणनीतिक तेल भंडार व्यवस्थाओं का विस्तार करने के लिए प्रमुख भागीदारों के साथ काम करने का संकल्प लिया। इस संदर्भ में, अमेरिकी पक्ष ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।

16. नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने और हमारी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप, भारत को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आपूर्ति विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत प्राकृतिक गैस, ईथेन और पेट्रोलियम उत्पादों सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की जबरदस्त

गुंजाइश और अवसर को रेखांकित किया। नेताओं ने विशेष रूप से तेल और गैस बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और दोनों देशों की ऊर्जा कंपनियों के बीच अधिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

17. नेताओं ने बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह से साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु रिएक्टरों के लिए परमाणु क्षति अधिनियम (सीएलएनडीए) के लिए नागरिक दायित्व में संशोधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में बजट घोषणा का स्वागत किया और आगे सीएलएनडीए के अनुसार द्विपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया, जो नागरिक दायित्व के मुद्दे को संबोधित करेगा और परमाणु रिएक्टरों के उत्पादन और तैनाती में भारतीय और अमेरिकी उद्योग के सहयोग को सुविधाजनक बनाएगा। यह आगे का रास्ता बड़े अमेरिकी-डिजाइन किए गए रिएक्टरों के निर्माण की योजनाओं को अनलॉक करेगा और उन्नत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन को विकसित करने, तैनात करने और बढ़ाने के लिए सहयोग को सक्षम करेगा। प्रौद्योगिकी और नवाचार

18. नेताओं ने यू.एस.-भारत ट्रस्ट ("रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों को बदलना") पहल की शुरुआत की घोषणा की, जो रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को उत्प्रेरित करेगी, जबकि सत्यापित प्रौद्योगिकी विक्रेताओं के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा की जाए।

19. "ट्रस्ट" पहल के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में, नेताओं ने वर्ष के अंत तक एआई अवसंरचना में तेजी लाने पर यू.एस.-भारत रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए यू.एस. और भारतीय निजी उद्योग के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर यू.एस.-मूल एआई अवसंरचना को वित्तपोषण, निर्माण, शक्ति प्रदान करने और मील के पत्थर और भविष्य की कार्यवाहियों के साथ जोड़ने में बाधाओं की पहचान की गई। अमेरिका और भारत अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों में उद्योग भागीदारी और निवेश को सक्षम करने, एआई के लिए कंप्यूट और प्रोसेसर के विकास और पहुंच पर सहयोग, एआई मॉडल में नवाचारों और सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए एआई अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे, जबकि इन प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा और नियामक बाधाओं को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा और नियंत्रण को संबोधित करेंगे।

20. नेताओं ने इंडस इनोवेशन के शुभारंभ की घोषणा की, जो सफल इंडस-एक्स प्लेटफॉर्म के बाद तैयार किया गया एक नया नवाचार पुल है, जो अमेरिका-भारत उद्योग और शैक्षणिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा और अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा ताकि नवाचार में अमेरिका और भारत का नेतृत्व बनाए रखा जा सके और 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेताओं ने इंडस-एक्स पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया, जो हमारी सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षमता का उत्पादन करने के लिए अमेरिकी और भारतीय रक्षा कंपनियों, निवेशकों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है, और 2025 में अगले शिखर सम्मेलन का स्वागत किया।

21. नेताओं ने ट्रस्ट पहल के हिस्से के रूप में, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, उन्नत सामग्रियों और फार्मास्यूटिकल्स सहित विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए भी प्रतिबद्धता

जताई। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, नेताओं ने महत्वपूर्ण दवाओं के लिए सक्रिय दवा सामग्री के लिए अमेरिका सहित भारतीय विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। ये निवेश अच्छी नौकरियां पैदा करेंगे, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाएंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में जीवन रक्षक दवाओं की कमी के जोखिम को कम करेंगे।

22. उभरती प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अनुसंधान और विकास में सहयोग में तेजी लाएंगे और संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देंगे, साथ ही खनिज सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों सदस्य हैं। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, लाभकारीकरण और प्रसंस्करण के साथ-साथ पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस उद्देश्य से, नेताओं ने रणनीतिक खनिज पुनर्प्राप्ति पहल की शुरुआत की घोषणा की, जो एल्युमिनियम, कोयला खनन और तेल और गैस जैसे भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी सहित) को पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए एक नया यू.एस.-भारत कार्यक्रम है।

23. नेताओं ने 2025 को अमेरिका-भारत नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अग्रणी वर्ष बताया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लाने के लिए AXIOM के माध्यम से NASA-ISRO के प्रयास की योजना है, और संयुक्त "NISAR" मिशन का शीघ्र प्रक्षेपण, दोहरे रडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप से मैप करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन है। नेताओं ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अधिक सहयोग का आह्वान किया, जिसमें लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा और ग्रह संरक्षण सहित उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता और पेशेवर आदान-प्रदान को साझा करना शामिल है। नेताओं ने पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों जैसे कनेक्टिविटी, उन्नत अंतरिक्ष उड़ान, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष स्थिरता, अंतरिक्ष पर्यटन और उन्नत अंतरिक्ष विनिर्माण में उद्योग की भागीदारी के माध्यम से वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

24. नेताओं ने अमेरिकी और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के महत्व को रेखांकित किया, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और भारतीय अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बीच एक नई साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी सेमीकंडक्टर, कनेक्टेड वाहन, मशीन लर्निंग, अगली पीढ़ी के दूरसंचार, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली और भविष्य के जैव विनिर्माण के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को सक्षम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और कई भारतीय विज्ञान एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग पर आधारित है।

25. नेताओं ने निर्धारित किया कि उनकी सरकारें निर्यात नियंत्रणों को संबोधित करने, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को संबोधित करते हुए हमारे दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधाओं को कम करने के प्रयासों को दोगुना कर देंगी। नेताओं ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के अतिसंकेंद्रण का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले तीसरे पक्षों द्वारा निर्यात नियंत्रण में अनुचित प्रथाओं की आम चुनौती का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया।

बहुपक्षीय सहयोग

26. नेताओं ने पुष्टि की कि अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए केंद्रीय है। और बेरोकटोक वैध वाणिज्य; तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत।

27. प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति ट्रम्प की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं, जिसके पहले नेता प्राकृतिक आपदाओं के लिए नागरिक प्रतिक्रिया का समर्थन करने और अंतर-संचालन में सुधार के लिए समुद्री गश्ती के लिए साझा एयरलिफ्ट क्षमता पर नई क्वाड पहलों को सक्रिय करेंगे।

28. नेताओं ने सहयोग बढ़ाने, राजनयिक परामर्श बढ़ाने और मध्य पूर्व में भागीदारों के साथ ठोस सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आर्थिक गलियारों में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला। नेताओं ने 2025 में नई पहलों की घोषणा करने के लिए अगले छह महीनों के भीतर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर और I2U2 समूह के भागीदारों को बुलाने की योजना बनाई है।

29. अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में विकासात्मक, मानवीय सहायता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका की सराहना करता है। इस संदर्भ में, नेताओं ने विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय वार्ता और सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और आर्थिक संपर्क और वाणिज्य में समन्वित निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया द्विपक्षीय, संपूर्ण-सरकार मंच, हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम शुरू किया। हिंद महासागर में अधिक संपर्क का समर्थन करते हुए, नेताओं ने मेटा की एक अंडरसी केबल परियोजना में बहु-अरब डॉलर, बहु-वर्षीय निवेश की घोषणा का भी स्वागत किया, जो इस साल काम करना शुरू कर देगी और अंततः पांच महाद्वीपों को जोड़ने और हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे वैश्विक डिजिटल राजमार्गों को मजबूत करने के लिए 50,000 किलोमीटर से अधिक तक फैलेगी। भारत विश्वसनीय विक्रेताओं का उपयोग करके हिंद महासागर में अंडरसी केबल के रखरखाव, मरम्मत और वित्तपोषण में निवेश करने का इरादा रखता है।

30. नेताओं ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में संबंधों, वाणिज्य और सहयोग को बढ़ाने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर, मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत में नई बहुपक्षीय एंकर साझेदारी बनाने की आवश्यकता को पहचाना। नेताओं को उम्मीद है कि वे 2025 की शरद ऋतु तक इन उप-क्षेत्रों में नई साझेदारी पहल की घोषणा करेंगे।

31. नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय सेटिंग्स में सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया। नेताओं ने अरब सागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद के लिए संयुक्त समुद्री बल नौसैनिक टास्क फोर्स में भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभाने के भारत के निर्णय की सराहना की।

32. नेताओं ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि आतंकवाद के वैश्विक संकट से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सहित आतंकवादी समूहों से आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। हमारे नागरिकों को नुकसान पहुँचाने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की साझा इच्छा को स्वीकार करते हुए, अमेरिका ने घोषणा की कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। नेताओं ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट

हमलों के अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उसके क्षेत्र का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न किया जाए। नेताओं ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलीवरी प्रणालियों के प्रसार को रोकने और आतंकवादियों और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा ऐसे हथियारों तक पहुँच को रोकने के लिए मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया।

लोगों के बीच सहयोग

33. राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के महत्व पर ध्यान दिया। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि 300,000 से अधिक भारतीय छात्र समुदाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना 8 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान करते हैं और कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन में मदद करते हैं। उन्होंने माना कि छात्रों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिभा प्रवाह और आवागमन ने दोनों देशों को परस्पर लाभान्वित किया है। नवाचार को बढ़ावा देने, सीखने के परिणामों में सुधार और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के महत्व को पहचानते हुए, दोनों नेताओं ने संयुक्त/दोहरी डिग्री और ट्विनिंग कार्यक्रमों, संयुक्त उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और भारत में यू.एस. के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अपतटीय परिसरों की स्थापना जैसे प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया।

34. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के वैश्विक कार्यस्थल में बदलने के लिए अभिनव, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित गतिशीलता ढांचे को लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, नेताओं ने छात्रों और पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता के लिए रास्ते को सुव्यवस्थित करने और अल्पकालिक पर्यटक और व्यावसायिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, साथ ही दोनों देशों के लिए आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुरे लोगों, आपराधिक सुविधाकर्ताओं और अवैध आव्रजन नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अवैध आव्रजन और मानव तस्करी को आक्रामक रूप से संबोधित किया।

35. नेताओं ने अवैध आव्रजन नेटवर्क, संगठित अपराध सिंडिकेट, जिसमें नार्को-आतंकवादी मानव और हथियार तस्कर शामिल हैं, के साथ-साथ अन्य तत्व जो सार्वजनिक और राजनयिक सुरक्षा और दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं, के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई।

36. राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधान मंत्री मोदी ने हमारी सरकारों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच उच्च-स्तरीय जुड़ाव बनाए रखने और एक स्थायी भारत-अमेरिका संबंधों के लिए अपने महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने का संकल्प लिया। साझेदारी जो हमारे लोगों की उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाती है, वैश्विक भलाई के लिए काम करती है, और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत में योगदान देती है।